

T+1 Settlement :-

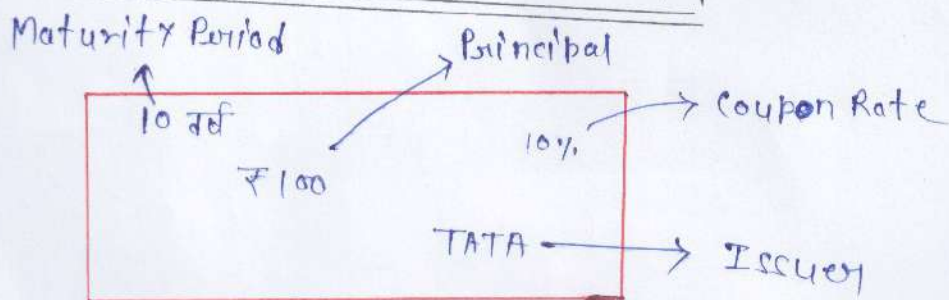
भारत में शर्कितरी के द्वितीयक बाजार (Secondary-Market) (सेपर बाजार) की वर्तमान Settlement प्रणाली जिसमें शर्कितरी के लेन-देन के दिन (T) से ठीक आगे आने वाले दिन (T+1) में उसका अन्तिम रूप से निपटान (Settlement) कर दिया जाता है।

Note:-

वर्तमान में SEBI के द्वारा T+0 Settlement व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव किया जाना बांड और डिबेंचर (bonds and debentures) :-

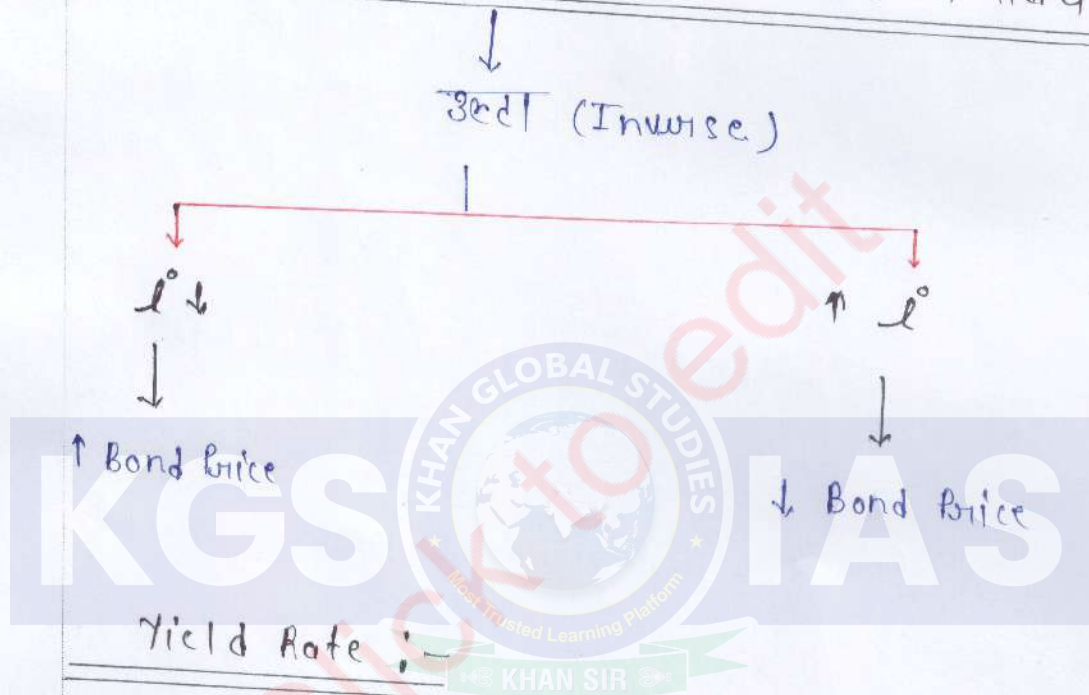
दोनों त्रचण जुटाने के उपकरण होते हैं लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बांड Secured होते हैं जबकि debentures unsecured होते हैं।

किसी भी बांड को मूल प्रारूप :-



Absolute Return = ₹ 10
(Per Year)

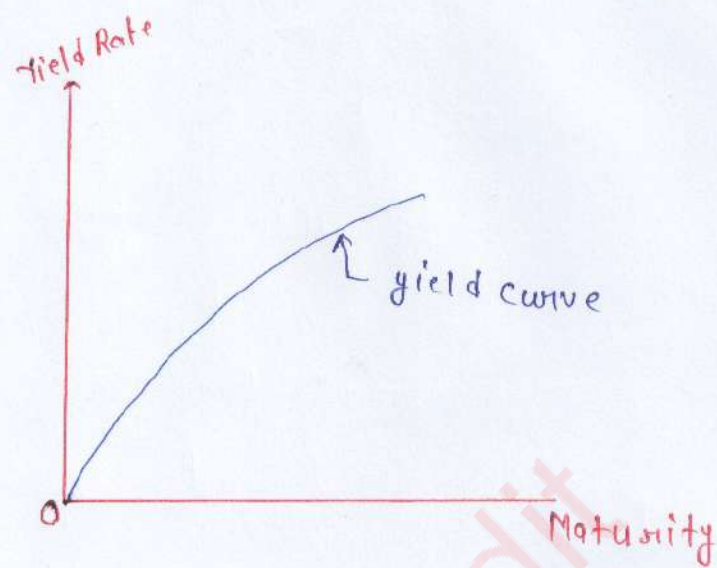
बांड की कीमत और बाजार की ब्याज दर में संबंध :-



$$\frac{\text{Absolute Return}}{\text{Market Price of bond}} \times 100$$

Yield Curve :-





Zero Coupon Bond (ZCB)

ऐसे बांड जिनकी कूपन रेट शून्य होती है।
 इन्हें **Deep Discount Bonds** भी कहते हैं।

Zero coupon Zero Principal (ZCZP) Bonds

सामाजिक संगठन इन्हें जारी कर सकते हैं
 (Social Stock Exchange के अन्तर्गत)
 इसके अन्तर्गत न केवल कूपन रेट शून्य होती है
 बल्कि मूलधन भी वापस नहीं दिया जाता है।

Junk Bonds :-

ये अल्पधिक जोखिम भरे बांड होते हैं लेकिन इसकी कूपन दर साधारण होती है।

Masala Bond (मसाला बांड) :-

विदेशों में जारी किये

जाने वाले RPBs (Rupee Dominated Bonds)

मसाला बांड शब्द का प्रयोग पहली बार विश्व बैंक की सहायक संस्था IFC - (International Finance Corporation) के द्वारा किया गया था।

Maharaja's Bonds :-

IFC (International Finance Corporation) द्वारा भारत में निकाले गये RPBs

Green Bonds :-

Green projects

जैसे- Solar energy, wind energy आदि के वित्तियन के लिए निकाले जाने वाले बांड।

SGBs - Sovereign Green Bonds :-

भारत सरकार द्वारा पहली बार 2023 में इन्हें निकाला गया।
शत सन्दर्भ में निम्न दो बांड निकाले गए-

(i) SGB - 28

↓

5-वर्षीय

(ii) SGB - 33

↓

10 वर्षीय

Greenium

सामान्य बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड (एक समान maturity) की Yield Rate में अंतर।

Panda Bonds :-

विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में Renminbi/Yuan में निकाले जाने वाले बांड।

Convertible Bonds :-

ऐसे बांड जो निवेशकों को एक निश्चित समय के बाद शक्ति में परिवर्तन का विकल्प देते हैं।

ये बांड मुद्रास्फीति के विरुद्ध Hedging प्रदान करते हैं जिसके कारण इनकी ब्याज दर अन्य Bonds की तुलना में कम होती है

Inflation-Indexed Bond :-

ऐसे बांड जो एक निश्चित वास्तविक ब्याज दर देते हैं और inflation के अनुसार कूपन रेट को समायोजित करते रहते हैं।

$$\text{Real Rate of Interest} = \text{Nominal Rate of Interest} - \text{Inflation rate}$$

(i) 3%	=	8%	-	5%
(ii) 3%	=	4%	-	1%
(iii) 3%	=	3%	-	-2% 0

Electoral Bond : Notified in 2018 :-

- (i) Political Funding के लिए किये गए।
- (ii) वाहक चेक की तरह होना

- (iii) देने वाले का नाम नहीं लिखा रहता है (बन्ड पर)
- (iv) SBI से मिलता है ।
- (v) 15 दिन तक valid रहता है ।
- (vi) चुनावी समय को छोड़कर
प्रत्येक तिमाही के शुरूआती 10 दिनों में खरीदा
जा सकता है

Note:-

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा
दिया गया है ।

KGS



IAS